सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

Pib, (17 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट को मंजूरी दी है।
- गृह मंत्रालय ने कार्यबल का गठन इसलिए किया था, ताकि सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्षेत्रों की निशानदेही की जा सके।
- कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) ने किया और उसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बलों, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
- गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु निम्न क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है:

- द्वीप विकास
- सीमा सुरक्षा
- संचार और नौवहन
- जीआईएस और संचालन आयोजन प्रणाली
- सीमा संरचना विकास

मुख्य बिंदु

- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसे पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके लिए इसरो और रक्षा मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग किया जाएगा।
- सीमा प्रहरी बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। लघु कालीन आवश्यकताओं के तहत सीमा प्रहरी बलों के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिए बैंडविथ का प्रबंध किया जाएगा।
- मध्यम अवधि की आवश्यकता के मद्देनजर इसरो एक उपग्रह लांच कर रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा।
- दीर्घकालीन अवधि के तहत गृह मंत्रालय नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा, ताकि अन्य एजेंसियां उपग्रह संसाधनों को साझा कर सकें।
- दूरदराज के इलाकों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपग्रह संचार की सुविधा दी जाएगी।
- इस परियोजना से द्वीपीय एवं सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और सीमा एवं द्वीपीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी।
- इसरो गृह मंत्रालय के लिए एक विशिष्ट उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, ताकि उसे अन्य देशों से लगी अपनी सीमाओं को और मजबूत बनाने में मदद मिल सके।

वाइब्रेंट गुजरात समिट

टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, (17 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन के 9वें संस्करण का गाँधी नगर में उद्घाटन किया।
- यह शिखर सम्मेलन गुजरात के गाँधी नगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम 'शेपिंग ऑफ ए न्यू इंडिया' है।
- वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन 18 से 20 जनवरी, 2019 तक किया जा रहा है।
- वाइब्रेंट गुजरात समिट के हिस्से के रूप में कई प्रमुख कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा इस शिखर सम्मेलन का नौवां संस्करण अनेक पूर्णरूपेण नए मंचों (फोरम) के शुभारंभ का भी साक्षी बनेगा।
- इसका उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन के दौरान ज्ञान साझा करने के स्वरूप में विविधता लाना और प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग के स्तर को बढ़ाना है।

क्या है?

- वाइब्रेंट गुजरात समिट की परिकल्पना वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी, जो उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे।
- इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात को फिर से एक पसंदीदा निवेश गंतव्य या राज्य के रूप में स्थापित करना था।
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और प्रभावकारी साझेदारियां करने से जुड़े एजेंडे पर विचार मंथन करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।

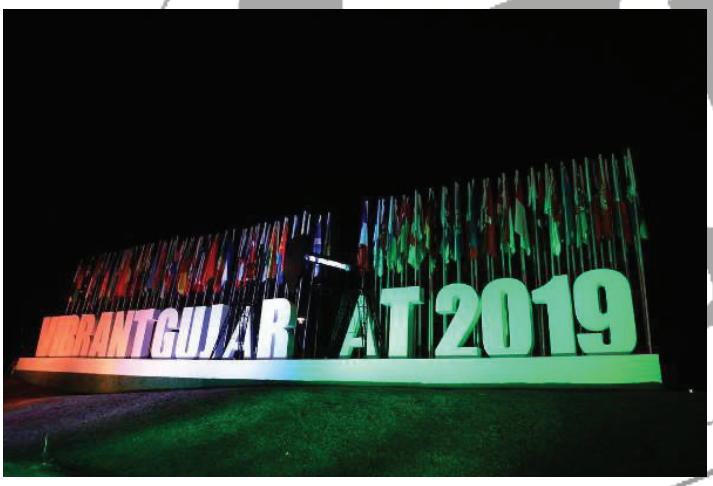

मुख्य बिंदु

- इस सम्मेलन में करीब 15 लाख लोग और 100 से ज्यादा देशों के 3000 प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है।
- वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन राज्य की राजधानी के एक मैदान के लगभग दो लाख वर्गमीटर क्षेत्र में हो रहा है।
- इस कार्यक्रम में लगभग 25 औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- इस शिखर सम्मेलन के द्वारा गुजरात में व्यापारिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

इसके सहभागी देश

- वाइब्रेंट गुजरात के पार्टनर देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पौलेंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, यूएई, उज्बेकिस्तान हैं।

भारत और जेआईसीए के बीच ऋण समझौता

Pib, (16 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में जापान के सरकारी विकास सहायता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह ऋण जापान ऑफिशिएल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा।

जापान द्वारा ऋण

- जापान द्वारा यह ऋण 40.074 बिलियन जापानी येन (लगभग 2470 करोड़ रुपये) की लागत से चेन्नई बाहरी रिंग रोड (चरण-1) के निर्माण के लिए हैं तथा 15000 बिलियन जापानी येन (लगभग 950 करोड़ रुपये) की लागत भारत में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्य के लिए हैं।

परियोजना का उद्देश्य

- चेन्नई बाहरी रिंग रोड (चरण-1) निर्माण परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगर क्षेत्र में बढ़ते यातायात की मांग को पूरा करना है, जिसे चेन्नई बाहरी रिंग रोड (सेक्टर-1) बनाकर तथा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट प्रणाली स्थापित करके किया जा सकता है।
- इससे यातायात भीड़-भाड़ में कम होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

- जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी एक सरकारी एजेंसी है जो जापान सरकार के लिए आधिकारिक विकास सहायता का समन्वय करती है।
- यह विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण काम करती है।

जापान-भारत सहकारी कार्यों का उद्देश्य

- भारत में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों का उद्देश्य भारत में एसडीजी के प्रोत्साहन में

योगदान करना, विशेषकर भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन देकर सामाजिक विकास करना और नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
- इससे 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत को मद्द मिलेगी।

सीमा सुरक्षा के लिए विशेष उपग्रह की घोषणा

इकोनॉमिक टाइम्स, (18 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा यह घोषणा की गई कि वह गृह मंत्रालय के लिए एक विशिष्ट उपग्रह प्रक्षेपित करेगा।
- उपग्रह का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अन्य देशों से सटी भारत की सीमा को और मजबूत बनाना है।
- गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह कदम सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर एक कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों का हिस्सा है।

लाभ

- इस परियोजना से द्वीपीय एवं सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
- सीमा एवं द्वीपीय क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे के विकास में मद्द मिलेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा।

रक्षा औद्योगिक गलियारा

इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैण्डर्ड, (19 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defence Industrial Corridor) का उद्घाटन किया।
- इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा नाम दिया गया है।
- इसमें तमिलनाडु के पाँच शहर शामिल किए जाएंगे।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन रक्षा गलियारों के विकास से एक सुनियोजित एवं सक्षम औद्योगिक आधार तैयार होगा, जिससे देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी।

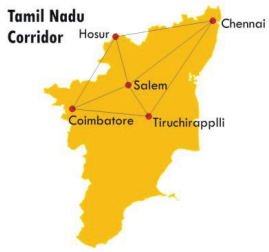

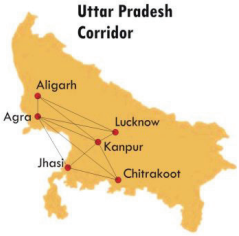

क्या है?

- इस रक्षा गलियारे में कुल 3,038 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा जिसमें सरकारी कंपनियों द्वारा सबसे अधिक निवेश किया जाएगा।
- ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड द्वारा क्रमशः 2,305 करोड़, 140.5 करोड़ और 150 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र की टीवीएस, डाटा पैटर्न और अल्फा डिजाइन क्रमशः 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
- रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल लॉकहीड मार्टिन ने भी इसमें निवेश करने की इच्छा जताई है।
- इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को निजी भागीदारों के लिए खोलना है और भारत में उपकरण बनाना तथा उसका विदेश में निर्यात करना है।

पृष्ठभूमि

- वित्तमंत्री ने 02 फरवरी, 2018 को बजट पेश करते समय देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे की स्थापना की घोषणा की थी।

- रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने का उद्देश्य विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाईयों के बीच संपर्क तय करना है।
- पिछले साल 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का अलीगढ़ में उद्घाटन हुआ था, जिसमें 3,732 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई थी।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे एक प्रकार से भारतीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी है और यह घरेलू बाजार सहित विदेशी बाजारों के लिए भी लाभदायक है।

भौगोलिक दृष्टिकोण

- तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा, जिसे तमिलनाडु रक्षा उत्पादन परिसर के नाम से भी जाना जाता है, एक नोडल साइट है।
- यह चतुष्कोणीय क्षेत्र है, जिसके केंद्र में तिरुचिरापल्ली है और उसके चारों ओर चेन्नई, होसूर, सालेम और कोयंबटूर शहर हैं।
- रक्षा गलियारों के विकास से एक सुनियोजित एवं सक्षम औद्योगिक आधार तैयार होगा, जिससे देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी।

प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, (19 Jan.)

संदर्भ

- ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्ष 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में ब्रिटेन को पछाड़ सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार एक ही स्तर के विकास और कमोवेश समान आबादी की वजह से इस सूची में ब्रिटेन और फ्रांस आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन यदि भारत इस सूची में आगे निकलता है तो उसका स्थान स्थायी रहेगा।

मुख्य बिंदु

- पीडब्ल्यूसी की वैश्विक अर्थव्यवस्था निगरानी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019 में ब्रिटेन की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत, फ्रांस की 1.7 प्रतिशत तथा भारत की 7.6 प्रतिशत रहेगी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और फ्रांस वर्ष 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे। इससे वैश्विक रैंकिंग में ब्रिटेन पांचवें स्थान से फिसलकर सातवें पायदान पर पहुंच जाएगा।
- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में भारत 2,590 अरब डॉलर के बराबर के जीडीपी के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। उसने फ्रांस को पीछे छोड़ा था। फ्रांस का जीडीपी 2,580 अरब डॉलर था।
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष 2019 में सुस्त रहेगी।
- दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर ने वर्ष 2016 के अंत तथा वर्ष 2018 के शुरू में जो रफ्तार पकड़ी थी, अब वह पूरी हो चुकी है।

प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स क्या है?

- पीडब्ल्यूसी वैश्विक अर्थव्यवस्था निगरानी रिपोर्ट एक लघु प्रकाशन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुख और मुद्दे पर गौर करता है।
- साथ ही यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर ताजा अनुमान प्रकाशित करता है।
- यह फर्म वर्ष 1998 में दो बड़ी कंपनियों-प्राइसवॉटर हाउस और कूपर्स एण्ड लाइब्रैंड के विलय के बाद बनायी गयी।

वास्तुकला की वैश्विक राजधानी

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (19 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी-2020 घोषित किया गया है।
- यह घोषणा यूनेस्को के सहायक महानिदेशक एर्नेस्तो ओटोन आर, अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला संघ के अध्यक्ष थॉमस वोनिएर एवं रियो की म्युनिसिपल सेक्रेटरी वेरेना विसेंती द्वारा 18 जनवरी, 2019 को की गई।

घोषणा का महत्व

- इस खिताब का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वास्तुकला स्मारकों को संरक्षित करना है जिसके तहत उन शहरों का चुनाव किया, जायेगा जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
- वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित होने के बाद रियो डी जेनेरियो विभिन्न कार्यक्रमों और विकास कार्यों से संस्कृति और वास्तुकला को संरक्षित करने के उपायों को दिखाएगा।
- इस माध्यम से विश्व में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, शहरी नियोजन और वास्तुकला के दृष्टिकोण से वैश्विक चर्चा को बल प्राप्त होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- रियो डी जेनेरियो शहर करीब दो शताब्दियों तक ब्राजील की राजधानी बना रहा, 1763 से 1822 तक पुर्तगाली औपनिवेशिक काल के दौरान और फिर 1822 से 1960 तक ब्राजील के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय के बाद।
- रियो डी जेनेरियो अपनी प्राकृतिक अवस्थिति, अपने कार्निवल उत्सव - साम्बा और अन्य संगीत तथा समुद्री तटों के कारण भी आकर्षण का कारण है।
- समुद्र तट के अलावा यहां के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में शामिल है- कोरकोवाडो पर्वत पर स्थित ईसा मसीह की विशाल मूर्ति - क्राईस्ट द रिडीमर।
- वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी रियो डी जेनेरियो द्वारा की गई। यह खेल आयोजित करने वाला यह दक्षिण अमेरिका का पहला शहर है।
- रियो डी जेनेरियो विश्व के सबसे बड़े शहरी वन क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु निम्नलिखित में से कौन-से क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं?

1. द्वीप विकास
2. सीमा सुरक्षा
3. संचार और नौवहन
4. जी आई एस और संचालन आयोजना प्रणाली
5. सीमा संरचना विकास

कूट:

(a) 2, 4 और 5 (b) 1, 3 और 5
(c) 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

2. 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम 'शेपिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड' है।
2. यह इस शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2003 में की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. हाल ही में भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के मध्य ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत-जापान सहकारी कार्यों का उद्देश्य भारत में एसडीजी (SDG) के प्रोत्साहन में योगदान करना है।
2. यह ऋण इंडिया ऑफिशिएल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. हाल ही में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा नाम दिया गया है।
2. इस गलियारे में सरकारी कंपनियों द्वारा सबसे अधिक निवेश किया जाएगा।
3. इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को निजी भागीदारों के लिए खोलना है और भारत में उपकरण बनाना तथा उसका विदेश में निर्यात करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. हाल ही में प्राइसवॉटर हाउस कूपर्स (PWC) की रिपोर्ट जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. PWC दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

Committed To Excellence

2. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन को पीछे छोड़ सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. हाल ही में चर्चा में रहे 'रियो डी जेनेरियो' शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूनेस्को द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी- 2020 घोषित किया गया है।
2. ईसामसीह की विशाल मूर्ति-क्राईस्ट द रिडीमर इसी शहर में स्थित है।
3. वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला यह दक्षिण अमेरिका का पहला शहर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 3 (b) 1 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

नोट : 16 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b), 3(d), 4(c), 5(d), होगा।

GS World
Committed To Excellence